

प्रेषक,

आर०के०मिश्र

अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन.

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक

नियोजन एवं वित्तीय प्रबंधन

उत्तराखण्ड, देहरादून.

वन एवं पर्यावरण अनुभाग-2

देहरादून : दिनांक ०५ मार्च, 2009

विषय:- अनुदान सं०-27 के जिला सैक्टर आयोजनागत पक्ष की योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 2008-09 की वित्तीय स्वीकृति.

महोदय,

उपरोक्त विषयक अपाके पत्र सं०-नि०११३/३५-१-बी दिनांक 23 जनवरी, 2009 के कम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वन विभाग के अंतर्गत संचालित वन संचार साधन योजना के अन्तर्गत पूर्व में अवमुक्त धनराशि रु० 4,50,00,000/- के अतिरिक्त संलग्न आय-व्ययक प्रपत्र-15 पर अंकित विवरण अनुसार रु० 33,99,000/- (रु० तैतीस लाख निन्यानवे हजार मात्र) की धनराशि पुनर्विनियोग करते हुए व्यय हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों एवं प्रतिबंधों के अधीन प्रदान करते हैं:-

1. धनराशि का आहरण / व्यय वास्तविक आवश्यकता अनुसार किस्तों में किया जाय.
2. उक्त स्वीकृत व्यय चालू योजनाओं पर ही किया जाय और किसी भी दशा में उक्त धनराशि का उपयोग नये कार्य के कार्यान्वयन के लिए न किया जाय. विभिन्न मदों में व्यय से पूर्व वित्त अनुभाग-1 के शासनादेश सं०-267/XXVII(1)/2008, दिनांक 27 मार्च, 2008, तथा वित्त विभाग के पत्र सं०-326/XXVII(1)/2008, दिनांक 23 अप्रैल, 2008 द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार सक्षम स्तर की अनुमति / यथा स्थिति शासन का अनुमोदन प्राप्त कर ही किया जाय. निर्माण कार्य सम्बन्धी आगणनों पर सक्षम स्तर का अनुमोदन पूर्व में ही प्राप्त कर लिया जाय तथा यथा-आवश्यकता नियमानुसार प्रशासनिक स्वीकृति पृथक से प्राप्त की जाय. बी.एम.-13, 17 पर धनराशि व्यय / अवमुक्ति सम्बन्धी सूचनायें एवं विवरण समयबद्ध आधार पर शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय. किसी भी शासकीय व्यय हेतु उत्तराखण्ड प्रोक्यूरमेन्ट नियमावली, 2008, वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-1 (वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन नियम), वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-पांच भाग-1 (लेखा नियम), वित्तीय हस्तपुस्तिका में अंकित सुसंगत नियमों/प्रतिबंधों, आय-व्ययक सम्बन्धी नियम (बजट मैनुअल), सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के शासनादेश तथा अन्य सुसंगत नियम, शासनादेश आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय.
3. योजना की विभिन्न मदों पर व्यय शासन के वर्तमान नियमों एवं आदेशों के अनुसार ही किया जाये तथा जहाँ आवश्यकता हो समक्ष स्तर से सहमति/स्वीकृति ली जाय.
4. क्षेत्र की योजना के सापेक्ष आवंटन अपने स्तर से किया जाय तथा धनराशि का आहरण यथा आवश्यकता ही किया जायेगा.
5. मितव्ययता के सम्बन्ध में नियमों का कड़ाई से पालन किया जाय.
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार एवं शासन के वित्त विभाग को वर्षान्त तक अवश्य उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय.
7. अप्रयुक्त धनराशि बजट मैनुअल के प्राविधानों के अन्तर्गत समय सारणी के अनुसार समर्पित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा.

क्रमशः.....2

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2008-09 के आय-व्यय अनुदान सं०-27 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2406-वानिकी तथा वन्य जीवन 01-वानिकी 800-अन्य व्यय 91-जिला योजना 01-वन संचार साधन की मानक मद 29-अनुरक्षण के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न पुनर्विनियोग के कॉलम-1 की वृत्तों से वहन किया जायेगा।

3. ये आदेश वित्त विभाग के अ०शा०सं०-181(P)/XXVII(4)/2008, दिनांक 28 फरवरी, 2009 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

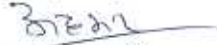
भवदीय

(आर०के०मिश्र)
अपर सचिव

संख्या-554(1)/X-2-2009, तददिनांकत.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं लेखा परीक्षा), उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून.
2. महालेखाकार(आडिट), उत्तराखण्ड, वैभव पैलस, सी-1/105, इन्दिरानगर, देहरादून.
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून.
4. सचिव, नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
5. अपर सचिव, वित्त अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून.
6. आयुक्त, कुमाऊँ / गढ़वाल मण्डल.
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड.
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, देहरादून.
9. सम्बन्धित मुख्य/वरिष्ठ/सम्बन्धित कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड.
10. बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन, सचिवालय, देहरादून.
11. प्रभारी, एन.आई.सी., उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
12. प्रभारी, मीडिया सेन्टर, उत्तराखण्ड सचिवालय, देहरादून.
13. गार्ड फाइल (जे).

आज्ञा से,

(अहमद अली)
अनु सचिव
